अच्छा बोलने से बेहतर है कि हम कुछ अच्छा करें।
– अज्ञात

'स्टार्ट अप इंडिया' का लाभ

महिला उद्यमी इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कुल 57 देशों में 52वां है। कर्जदाता प्लैटफॉर्म 'इनोवेन कैपिटल' के अनुसार वित्तपोषित स्टार्टअप कंपनियों में कम से कम एक महिला को–फाउंडर वाली कंपनियों का हिस्सा 2018 में कुल का 17 फीसदी था, जो 2019 में घटकर 12 प्रतिशत रह गया।

आरती सिंह।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'स्टार्ट अप इंडिया' का लाभ महिला उद्यमियों को ज्यादा नहीं मिल पाया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 के अनुसार इस साल 8 जनवरी तक 27,084 अधिकृत स्टार्टअप कंपनियों में कम से कम एक महिला डायरेक्टर वाली कंपनियों का हिस्सा महज 43 प्रतिशत था।

महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी कम है, जहां स्टार्टअप कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किए हैं। महिला उद्यमी इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कुल 57 देशों में 52वां है। कर्जदाता प्लैटफॉर्म 'इनोवेन कैपिटल' के अनुसार वित्तपोषित स्टार्टअप कंपनियों में कम से कम एक महिला को–फाउंडर वाली कंपनियों का हिस्सा 2018 में कुल का 17 फीसदी था, जो 2019 में घटकर 12 प्रतिशत रह गया। साफ है कि महिलाएं इस क्षेत्र में आना तो चाहती हैं लेकिन परिस्थितियां अनुकूल न रहने के कारण कुछ समय बाद वे अपने कदम वापस खींच ले रही हैं।

वैसे तो देश में सामाजिक स्थितियां महिलाओं के लिए कारोबार करने के अनुकूल नहीं बन पाई हैं, फिर भी कुछ वर्षों से इस दायरे में स्त्रियां दिखने लगी हैं। खासकर स्टार्टअप्स का दौर शुरू होने के बाद नई पीढ़ी की महिलाओं ने इसमें अपनी क्षमता सिद्ध की। कुछ ने इसमें सफलता भी पाई लेकिन उनके सामने चुनौतियां इतनी ज्यादा हैं कि कुछ दूर जाने के बाद उनका मनोबल टूट जा रहा है। सर्वे से पता चला है कि उन्हें क्रेडिट सपोर्ट भी कम मिलता है। एक अनुमान है कि महिलाओं के 3 फीसदी स्टार्टअप्स को ही फंड मिल पा रहा है। इसका एक कारण शायद यह भी है कि बाजार में स्वतंत्र महिला निवेशकों की मौजूदगी नाममात्र ही है। लेकिन बड़ा सच यह है कि लगातार मुनाफा कमाने की क्षमता, टिकाऊपन या फिर विस्तार की कसौटियों पर महिला उद्यमियों के स्टार्टअप्स को निवेशक ज्यादा जोखिम भरा मान रहे हैं। उन्हें फंड देते समय उनके कारोबार का आकलन करने के अलावा उनके परिवार का भी मूल्यांकन किया जाता है, जबकि पुरुषों के मामले में ऐसा नहीं है। पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ भी एक बड़ी बाधा है। इस दायित्व के चलते महिलाओं को पुरुषों की तुलना में नेटवर्किंग के लिए कम समय मिल पाता है। स्त्री को लेकर समाज के पूर्वाग्रह अलग आड़े आते हैं। महिला बॉस से पुरुषों का अहं कुछ ज्यादा ही टकराता है इसलिए हाल तक हुनरमंद लोगों को कंपनी में लाना महिला उद्यमियों के लिए एक बड़ी समस्या थी।

कई पुरुष प्रफेशनल्स इस दुविधा में रहते हैं कि महिला स्वामित्व वाला उद्यम चल पाएगा या नहीं। जिन वेंडरों के साथ उन्हें खरीद–बिक्री करनी होती है, वे भी महिला उद्यमी को गंभीरता से नहीं लेते। अगर हम कारोबारी दायरे में महिला–पुरुष बराबरी चाहते हैं तो इन सारे पहलुओं पर लगातार कुछ न कुछ करते रहना होगा।

बहस की चिंता

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

'बहस की चिंता मत कीजिए, सामने वाले का दिल जीत लीजिए। एक बार आपने उसका दिल जीत लिया तो वह खुद आपकी तरफ से तर्क करने लगेगा।' निर्दोष सी लगने वाली यह सलाह जो बुजुर्ग सज्जन दे रहे थे, उनकी विशाल हृदयता के वहां बैठे सभी लोग कायल थे। बात उस नागपुर शहर में हो रही थी, जिसे बेहिचक विचारों की त्रिवेणी कहा जा सकता है। आरएसएस का मुख्यालय तो यहां है ही, आंबेडकर की विचार परंपरा के भव्य स्मारक के रूप में दीक्षाभूमि भी यहां मौजूद है। वामपंथी विचारों का केंद्र यह शहर काफी पहले से रहा है। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित माने जाने वाले इलाकों के बीच स्थित यह सबसे बड़ा शहर है। लिहाजा दक्षिणपंथी, वामपंथी और दलित–तीनों विचार परंपराएं यहां इस शिद्दत से मिलती हैं कि हर गली, हर चौराहा और हर नुक्कड़ गंभीर बहस का केंद्र बना नजर आता है।

संपादकीय

सरकार का मुख्य प्रयास

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' एक ऐसी स्कीम है जिसे बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई है और इसे जरूरी भी माना जाता है। पर यह भी कटौती से नहीं बच सकी। इसके लिए मूल प्रावधान 280 करोड़ रुपये का था लेकिन संशोधित अनुमान में इसे 200 करोड़ रुपये कर दिया गया। किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य और भलाई के लिए 'सबला' स्कीम महत्वपूर्ण रही है। इसके लिए वर्ष 2019–20 में 300 करोड़ रुपये का मूल प्रावधान था, पर संशोधित अनुमान में इसे आधा कर दिया गया और मात्र 150 करोड़ रुपये पर पहुंचा दिया गया। माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं के प्रोत्साहन की स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपये का मूल प्रावधान था, जो संशोधित अनुमान में 88 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। बाल मजदूर राष्ट्रीय परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का मूल प्रावधान था। यह संशोधित अनुमान में 79 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' राज्यों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की गुणवत्ता के सुधार के लिए केंद्र सरकार का मुख्य प्रयास रहा है। इसके लिए 2,100 करोड़ रुपये का मूल प्रावधान था जो संशोधित अनुमान में 1,380 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को देखें तो यह आश्चर्यजनक स्थिति सामने आती है कि सबसे महत्वपूर्ण वर्ष 2019–20 में इसके वार्षिक बजट को आधे से भी कम कर दिया गया था। स्वच्छ भारत मिशन के लिए वर्ष 2019–20 में 2,650 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी लेकिन जब इस वर्ष के संशोधित अनुमान तैयार किए गए तो इसमें बड़ी कटौती कर इसे मात्र 1,300 करोड़ रुपये कर दिया गया। जाहिर है, महत्वपूर्ण परियोजनाओं और स्कीमों के संशोधित अनुमान तैयार करते समय जबर्दस्त कटौती हुई। ऐसी स्थिति में अहम क्षेत्रों के संदर्भ समझने के लिए इस पर पैनी निगाह रखना जरूरी है।

राहुल गांधी की सोच चाहे जो भी रही हो, लेकिन अगर उन्होंने लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद यह स्पष्ट कर दिया कि वह अब पार्टी अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते, तो पार्टी को अपने लिए कोई और अध्यक्ष चुनना ही होगा।

कांग्रेस के अंदर से आवाज

संजय भट्ट।

आखिरकार कांग्रेस के अंदर से आवाज उठनी शुरू हुई। फुसफुसाहटें कुछ समय पहले से सुनाई दे रही थीं, लेकिन पूर्व सांसद और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित ने वह बात खुल कर कह दी, जो थी तो सबके मन में, पर कोई जुबान पर नहीं ला रहा था। संदीप ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे पार्टी में नेतृत्वहीनता की स्थिति दूर करने की कोई पहल यह सोचकर नहीं कर रहे कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की सोच चाहे जो भी रही हो, लेकिन अगर उन्होंने लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद यह स्पष्ट कर दिया कि वह अब पार्टी अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते, तो पार्टी को अपने लिए कोई और अध्यक्ष चुनना ही होगा। देश की सबसे पुरानी पार्टी यह छोटी सी बात समझने को तैयार नहीं है।

राहुल गांधी के मना करने के बाद कांग्रेस ने अपना अंतरिम अध्यक्ष भी चुना तो सोनिया गांधी को, जिनका खराब स्वास्थ्य बतौर पार्टी अध्यक्ष उनकी सक्रियता में लगातार बाधक बना हुआ था। दिलचस्प बात यह कि अंतरिम अध्यक्ष की भूमिका में आने के बाद भी उनके पूर्णतरू स्वस्थ होने की बात कभी नहीं कही गई, फिर

भी नए अध्यक्ष के चयन की दिशा में कोई पहल उन्होंने अभी तक नहीं की है। सर्वोच्च स्तर पर मौजूद इस दुविधा और अनिश्चय का असर पिछले आम चुनाव के बाद हुए हर विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर पड़ा है।

झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में लगा ही नहीं कि पार्टी अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। लड़ाई मुख्यतरू स्थानीय नेताओं और पार्टी प्रत्याशियों के भरोसे छोड़ दी गई। इस रवैये का चरम बिंदु दिल्ली में दिखा, जहां 2013 तक सबसे ताकतवर मानी जाने वाली कांग्रेस महज चार फीसदी वोट पर सिमट गई, जो जमानत जब्ती से भी नीचे का प्रतिशत है। इसके बाद संदीप दीक्षित और शशि थरूर जैसे नेताओं की बेचैनी जरूर सामने आई, लेकिन पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व ने अब भी हरकत में आने का कोई संकेत नहीं दिया है। इससे संदेह होता है कि पार्टी आलाकमान को कांग्रेस से ज्यादा फिक्र कहीं पार्टी के शीर्ष परिवार की तो नहीं है।

जाहिर है, कांग्रेस के अंदर संकट उससे कहीं ज्यादा गंभीर है, जितना यह ऊपर से लगता है। पार्टी में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम कई लोग मौजूद हैं, यह बात खुद में बेमानी लगती है। ये सारे सक्षम लोग गांधी परिवार के किसी भी सदस्य का नेतृत्व सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, पर खुद यह जिम्मेदारी संभालने को इनमें से एक भी तैयार नहीं होता। कुछ मायनों में इससे मिलती–जुलती स्थिति से अभी आठ साल पहले तक बीजेपी भी गुजर रही थी, मगर उसे असमंजस से बाहर निकालने के लिए आरएसएस का नेतृत्व मौजूद था। कांग्रेस में तो ऐसा कोई बाहरी शक्ति केंद्र भी नहीं है। गांधी–नेहरू परिवार अगर कुछ दिन और अपनी दुविधा से पार नहीं पाता तो खुद को जिंदा रखने के लिए पार्टी को ही कुछ करना होगा।

अष्टयोग- 4956

		3				7
2	31		31		28	2
	2	1		3		4
3	34	6	31		33	
	5		3	2		1
5	31	5	32	7	38	3
			4			6

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4955 का हल

3	1	7	6	2	5	4
5	31	3	37	1	28	7
4	3	5	7	6	1	2
2	29	6	40	7	34	3
1	6	2	4	3	7	5
7	32	4	26	5	34	1
6	5	1	3	4	2	7

■ Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

महिलाओं को कमांड रोल दे दिया तो

मोहन। सेना के अधिकारियों के बीच यह भी चर्चा चल रही है कि अगर महिलाओं को कमांड रोल दे दिया तो फिर उन्हें पीस पोस्टिंग ही देनी पड़ेगी। ऐसे में पुरुष अधिकारियों को और उनके परिवार वालों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि पुरुष अधिकारियों के लिए पीस पोस्टिंग के कम मौके होंगे और उन्हें फील्ड पोस्टिंग में रहना होगा। सवाल यह है कि यह बात तय कैसे मानी जा रही है कि महिलाएं सिर्फ पीस पोस्टिंग में ही कमांड रोल निभाएंगी। हर सर्विस की अपनी कंडिशन होती है। सर्विस जॉइन करने से पहले सबको यह पता होता है। महिलाओं को अगर पहले से ही यह बताया जाए कि फील्ड पोस्टिंग और पीस पोस्टिंग में जेंडर का कोई फर्क नहीं रखा जाएगा तो वे यह तय कर सकती हैं कि वे उस रोल के लिए खुद को फिट पाती हैं या नहीं। कमांड रोल के दरवाजे एकदम बंद करने की बजाय उन्हें विकल्प दिया जा सकता है। देखा जा सकता है कि लगभग सभी दलीलों के पीछे वह सोच काम कर रही है जिसे हम पितृसत्तात्मक सोच के रूप में जानते–समझते आए हैं।